PRGI - UAHIN/25/A4862

तीसरी नजर

साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष-1 अंक-23 रुद्रपुर से प्रकाशित, बुद्धवार 01 जुलाई , 2026 पृष्ठ-4 मूल्य 2(रूपये)

उत्तराखण्ड को सड़क विकास की बड़ी सौगात, केंद्र ने दी हजारों करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी

देहरादून संवाददाता। नई दिल्लीध देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ध ाामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में उत्तराखण्ड से जुड़े सड़क एवं आधारभूत संरचना विकास के विभिन्न प्रस्तावों को रखा। बैठक में राज्य के लिए करीब 750 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत स्वीकृति देने पर सहमति बनी।इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी पांच प्रमुख परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 2966 करोड़ रुपये है। इनमें श्रीनगर बाईपास, पुरकाजी–लक्सर–हरिद्वार मार्ग की फोरलेनिंग, लोहाघाट और पिथौरागढ़ बाईपास, मझोला–खटीमा मार्ग का चार लेन विस्तार तथा रामनगर–रानीखेत (मोहन) मार्ग का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं।मुख्यमंत्री ने अर्धकुंभ 2027 को देखते हुए हरिद्वार बाईपास परियोजना को समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा कोटद्वार बाईपास के कार्यों में तेजी लाने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक



सहमति दी। इसके अलावा विभिन्न संपर्क मार्गों के विकास के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी देने पर भी सहमति बनी।बैठक में अल्मोड़ा सिकुड़ा बैंड से एनएच–309 तक सुरंग सहित मोटर मार्ग निर्माण की लगभग 300 करोड़ रुपये की परियोजना पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के उपचारात्मक कार्यों के लिए उत्तराखण्ड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर के माध्यम से डीपीआर तैयार करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की।मुख्यमंत्री धामी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तराखण्ड में सड़क संपर्क, पर्यटन, आपदा प्रबंधन और सीमांत क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी।

ऊधमसिंह नगर में मानसून की दस्तक, किच्छा में 70 मिमी बारिशय नदियां और जलाशय सामान्य स्तर पर

रुद्रपुर संवाददाता। ऊधमसिंह नगर जनपद में मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। जिला आपदा परिचालन केंद्र (डीईओसी) की 1 जुलाई 2026 की सुबह 8रू30 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार जिले में मौसम बादलों से घिरा हुआ है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में सबसे अधिक 70 मिमी वर्षा किच्छा क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा खटीमा में 30 मिमी, सितारगंज में 17 मिमी, रुद्रपुर में 9. 20 मिमी, गदरपुर में 6 मिमी, बाजपुर में 5.75 मिमी तथा काशीपुर में 5. 5 मिमी बारिश दर्ज की गई। जबकि जसपुर में वर्षा नहीं हुई। जिले की सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर फिलहाल सामान्य बना हुआ है। सुखीध बेगुल, कैलाश, जगबूड़ा, परवीन, देवहा, कामन, ढेला, फीका, गौला तथा कल्याणी नदियों में जल प्रवाह चेतावनी और खतरे के स्तर से काफी नीचे है। इसी प्रकार मुख्य शारदा नहर का जलस्तर भी सामान्य श्रेणी में बना हुआ है।जनपद के सभी प्रमुख जलाशयों और बांधों में भी स्थिति नियंत्रण में है। बेगुल, नानक सागर, शारदा सागर, बौर, हरिपुरा, तुमड़िया तथा धौरा जलाशयों का जलस्तर चेतावनी स्तर से नीचे दर्ज किया गया है। किसी भी जलाशय से असामान्य जल निकासी नहीं की जा रही है।जिला आपदा परिचालन केंद्र के अनुसार जनपद में सड़क, संचार, विद्युत और पेयजल आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है तथा कहीं से भी किसी प्रकार की आपदा या अवरोध की सूचना नहीं मिली है। प्रशासन द्वारा मौसम की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

मंत्री का नगर पालिका में छापा, गायब मिले कई अधिकारी व कर्मचारी

उधमसिंहनगर। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने जसपुर नगर पालिका परिषद में छापा मारा। छापे के दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जबकि कार्यालय परिसर में मदिरा सेवन से जुड़ी सामग्री मिलने पर मंत्री ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने सोमवार को नगर पालिका परिषद, जसपुर का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली का जायजा लिया। अचानक पड़े इस छापे से कार्यालय में हड़कंप मच गया। मंत्री ने सबसे पहले उपस्थिति पंजिका (अटेंडेंस रजिस्टर) की जांच की, जिसमें कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ कर्मचारी लगातार कई दिनों से कार्यालय नहीं आ रहे थे।मंत्री ने कार्यालय के विभिन्न अनुभागों का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी दौरान कार्यालय परिसर में मदिरा सेवन से संबंधित सामग्री (शराब की बोतलें) मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। मंत्री



ने इसे सरकारी कार्यालय की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कहा कि इस तरह का आचरण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।राम सिंह कैड़ा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में तत्काल नियमानुसार जांच कराई जाए तथा जो भी कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ बिना किसी देरी के आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही हर कर्मचारी की पहली जिम्मेदारी है। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है। यदि अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचेंगे या अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं करेंगे, तो इसका सीधा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही या गैरजिम्मेदाराना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

चाकू दिखाकर किशोरी से दुष्कर्म का आरोप

रुद्रपुर संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित की मां की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले एक किशोर पर आरोप लगाया है। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने पति और बच्चों के साथ रुद्रपुर क्षेत्र में रहती है। उनका आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला एक किशोर अक्सर उनकी नाबालिग बेटी को परेशान करता था। बीते दिनों दोपहर में परिवार का कोई सदस्य घर पर मौजूद नहीं था तभी आरोपी किशोर उनके घर में घुस गया। तहरीर के अनुसार आरोपी ने पहले किशोरी को चाकू दिखाकर डराया धमकाया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित ने विरोध ा कर खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी के हाथ में चाकू होने के कारण वह भयभीत हो गई। आरोप है कि घटना के बाद आरोपी ने किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी और वह वहां से चला गया। पीड़ित की मां जब घर पहुंची तो किशोरी ने सारी आपबीती मां को बताई, जिससे परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता की मां तत्काल रुद्रपुर कोतवाली पहुंची, जहां लिखित तहरीर में पड़ोस में रहने वाले किशोर पर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़ित की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पीड़ित परिवार ने मामले में पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग की है।

सम्पादकीय

राम मंदिर चंदा-चढ़ावा प्रकरण क्या सच तक पहुंचेगी जांच?

अयोध्या के राम मंदिर में चंदा–चढ़ावा और दान सामग्री की कथित चोरी का मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और पारदर्शिता से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय है। ऐसे मामले में जांच की प्रक्रिया जितनी निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित होनी चाहिए थी, उतने ही गंभीर सवाल अब जांच की दिशा और गति पर उठने लगे हैं।पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉ. विक्रम सिंह और सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक एम.एल. शर्मा जैसे अनुभवी अधिकारियों ने जांच में मौजूद खामियों की ओर संकेत किया है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि गिरफ्तार आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजने के बावजूद पुलिस ने उनकी रिमांड क्यों नहीं मांगी? किसी भी आर्थिक अपराध या चोरी के मामले में पूछताछ, बरामदगी और धन के स्रोत तथा उपयोग की जानकारी जुटाना जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यदि यह प्रक्रिया प्रभावी ढंग से नहीं अपनाई गई, तो सच तक पहुंचना कठिन हो सकता है।मामले को और उलझाने वाला तथ्य यह है कि प्रारंभिक स्तर पर कथित बरामदगी होने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने में लगभग 20 दिनों का विलंब हुआ। इस दौरान साक्ष्यों के प्रभावित होने या धन को ठिकाने लगाने की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।हालांकि किसी भी व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराने का अधिकार केवल जांच और न्यायालय को है, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि जांच निष्पक्ष दिखाई भी दे। राम मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। इसलिए इस प्रकरण में आधे–अधूरे उत्तर या अधूरी जांच से जनविश्वास को आघात पहुंच सकता है।आवश्यकता इस बात की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच हो, दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए तथा भविष्य में धार्मिक संस्थानों में प्राप्त चंदे और चढ़ावे के प्रबंधन के लिए मजबूत जवाबदेही तंत्र विकसित किया जाए। आस्था का सम्मान तभी सुरक्षित रहेगा, जब उसके साथ जुड़ी व्यवस्थाओं में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो।

संपादक भूपेश छिम्वाल

गर्भवती महिला की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत

–परिजनों ने की स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

चमोली। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) थराली से रेफर की गई एक गर्भवती महिला की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। कुराड़ गांव के आफर तोक की रहने वाली सरिता देवी (35 वर्ष) को प्रसव पीड़ा होने पर थराली अस्पताल लाया गया था, जहां से उन्हें उच्च केंद्र रेफर किया गया। लेकिन कर्णप्रयाग अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका के भाई पप्पू सोलियाल ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह 8 बजे जब उनकी बहन सरिता देवी (पत्नी नरेंद्र कुमार) को अस्पताल लाया गया, तब वह बिल्कुल स्वस्थ थीं।आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर की नाइट शिफ्ट होने के कारण उन्होंने करीब तीन घंटे की देरी से महिला का चेकअप किया। इसके बाद, अस्पताल में गायनोको लॉजिस्ट (महिला रोग विशेषज्ञ) न होने की बात कहकर दोपहर लगभग 3 बजे मरीज को रेफर किया गया। परिजनों का कहना है कि थराली से रेफर होने के बाद नारायणबगड़ के समीप महिला की हालत बिगड़ गई और उन्होंने एंबुलेंस में ही दम तोड़ दिया। भाई पप्पू सोलियाल ने एंबुलेंस व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि 108 एंबुलेंस में न तो ऑक्सीजन सिलिंडर चालू हालत में था और न ही पंखा चल रहा था।ग्राम प्रधान लेटाल, चमेली देवी ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए बताया कि सरिता देवी की मौत के बाद उनके दो बच्चे नितिन कुमार (15 वर्ष) और पायल (8 वर्ष) के सिर से मां का साया उठने के कारण बेसहारा हो गए हैं। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पीड़ित परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग और एंबुलेंस प्रबंधन के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

संविधान और सामाजिक न्याय की लड़ाई में कांग्रेस के विचार आज भी प्रासंगिक: प्रवीण डाबर

देहरादून संवाददाता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विचार विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टेन प्रवीण डाबर ने कहा कि वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों में कांग्रेस के मूल विचारकृसमता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता आज पहले से अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विचार विभाग की जिम्मेदारी केवल संगठनात्मक विमर्श तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में लोकतांत्रिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना भी है।वे देहरादून के राजीव भवन में उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस विचार विभाग द्वारा आयोजित "विचार से परिवर्तन, संविधान से राष्ट्र निर्माण" विषयक वैचारिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान देश और उत्तराखण्ड की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों पर व्यापक चर्चा हुई।बैठक की अध्यक्षता करते हुए उत्तराखण्ड कांग्रेस विचार विभाग के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप जोशी ने कहा कि राज्य बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संकट जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि विचार विभाग समाज के सामने तथ्यपरक और समाधान आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा।स्वागत उद्बोधन में डॉ. प्रेम बहुखण्डी ने संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर आधारित जनसंवाद को समय की आवश्यकता बताया। बैठक में युवाओं, महिलाओं, शिक्षकों और बुद्धिजीवियों के साथ संवाद बढ़ाने, सोशल मीडिया के माध्यम से वैचारिक अभियान चलाने तथा पलायन, रोजगार, शिक्षा, पर्यावरण, कृषि और पर्यटन जैसे विषयों पर व्यापक वैचारिक दस्तावेज तैयार करने पर विचार–विमर्श किया गया।बैठक में अनेक शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाग लिया। अंत में यह संकल्प लिया गया कि संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की भावना को जन–जन तक पहुंचाने के लिए नियमित अध्ययन, संवाद और जनजागरण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।



नशीले इंजेक्शनों की तस्करी पर अदालत का कड़ा फैसला, महिला तस्कर को 10 वर्ष का कठोर कारावास

रुद्रपुर संवाददाता। प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शनों की तस्करी से जुड़े छह वर्ष पुराने मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए महिला आरोपी शहनाज को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।अभियोजन पक्ष के अनुसार फरवरी 2020 में रम्पुरा चौकी पुलिस को सूचना मिली थी कि खेड़ा क्षेत्र स्थित चांद मस्जिद के आसपास एक महिला प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शनों की अवैध बिक्री कर रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों को साथ लेकर विशेष टीम गठित की और मौके पर घेराबंदी की। पुलिस को देखकर महिला भागने का प्रयास करने लगी, लेकिन उसे तत्काल पकड़ लिया गया।तलाशी के दौरान महिला के कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद हुईं। बरामद सामग्री में ब्यूप्रेनॉर्फिन के 108 इंजेक्शन, डायजापाम के 108 इंजेक्शन तथा एविल की 115 शीशियां शामिल थीं। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बरामदगी, जांच प्रक्रिया और अन्य तथ्यों से संबंधित गवाहों के बयान एवं दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के आरोपों को सिद्ध माना।विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) दीपाली शर्मा ने आरोपी शहनाज को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।करीब छह वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले को नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का कहना है कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

50 हजार की नकली खेप के साथ हरिद्वार पुलिस ने तीन को दबोचा

–बिजनौर से जुड़े तार, आरोपी ऑनलाइन मंगाते थे विशेष पेपर

–लैपटॉप, दो प्रिंटर, मोबाइल फोन और नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण किए बरामद

–पहले भी बिजनौर क्षेत्र में 60 हजार के नकली नोट बाजार में चला चुके आरोपी



हरिद्वार संवाददाता। पुलिस हरिद्वार ने घर में नकली नोट छापकर बाजार में खपाने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। दो दिन पहले 52,500 रुपये के नकली नोट बरामद होने के मामले की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस गिरोह की जड़ तक पहुंची और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 50 हजार रुपये के छपे नकली नोट, लैपटॉप, दो प्रिंटर, मोबाइल फोन और नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण बरामद किए। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पहले भी बिजनौर क्षेत्र में करीब 60 हजार रुपये के नकली नोट बाजार में चला चुके हैं। मामले में पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही है।एसपी सिटी क्राइम क्राइम निशा यादव ने मायापुर स्थित एसपी सिटी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कोतवाली श्यामपुर पुलिस ने बताया कि 27 जून को वनकर्मियों के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान आरोपियों की गाड़ी से 52,500 रुपये के नकली नोट भी बरामद किए थे। तीनों आरोपियों को जेल भेजने के बाद जांच आगे बढ़ाई गई। सीओ अवनी तिवारी ने मामले की विवेचना की और पूछताछ के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस को सूचना मिली कि गिरोह के सदस्य नकली नोट छापने में प्रयुक्त उपकरण और तैयार नकली नोटों को कार से लेकर बिजनौर के बढापुर की ओर ठिकाने लगाने जा रहे हैं।एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर पुलिस टीम ने लालढांग तिराहे के पास घेराबंदी कर बीते दिन कार को रोक लिया। तलाशी में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, एचपी और कैनन कंपनी के दो प्रिंटर, पांच मोबाइल फोन, 500 रुपये के चार असली नोट और 25 पेपर शीट बरामद किया, जिन पर 500 रुपये के करीब 50 हजार रुपये मूल्य के नकली नोट छपे हुए थे। इन नोटों की कटिंग की जानी बाकी थी। इसके अलावा नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला विशेष वॉटरमार्क पेपर भी बरामद किया गया।पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में देवेन्द्र कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी सरदारपुर छामली, थाना बड़ापुर, जिला बिजनौर, गुलजार अहमद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी टांडा सिक्कावाला, थाना बड़ापुर, जिला बिजनौर और शगुन जोशी पुत्र पवन जोशी निवासी लालढांग, थाना श्यामपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि गुलजार अहमद ऑनलाइन विशेष पेपर मंगाता था।शगुन जोशी असली नोट की फोटो लेकर उसे सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप की मदद से हाई क्वालिटी में तैयार करता था, ताकि प्रिंट बिल्कुल असली नोट जैसा दिखाई दे। इसके बाद प्रिंटर की मदद से नकली नोट छापे जाते थे। मुख्य आरोपी देवेन्द्र कुमार ने पूछताछ में बताया कि उसने और गुलजार ने पहले बिजनौर के बड़ापुर क्षेत्र में करीब एक लाख रुपये के नकली नोट छापे थे। इनमें कुछ नोट खराब हो गए, जबकि लगभग 60 हजार रुपये के नकली नोट बाजार में चला दिए गए। इससे मिले मुनाफे के बाद उन्होंने गिरोह का विस्तार किया और देवेन्द्र के जीजा शिवम तथा नोटों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए शगुन जोशी को भी अपने साथ जोड़ लिया।चारों मिलकर नकली नोट तैयार कर उन्हें बाजार में खपाने की साजिश को अंजाम दे रहे थे। गिरोह ने नकली नोट तैयार करने के लिए बाकायदा तकनीकी तरीका अपनाया था। ऑनलाइन विशेष पेपर मंगाया जाता था। असली नोट की हाई रिजॉल्यूशन फोटो लेकर सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप के जरिए उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाती थी। इसके बाद लैपटॉप और हाई क्वालिटी प्रिंटर से नोट छापे जाते थे। तैयार नोटों की कटिंग कर उन्हें बाजार में खपाने की तैयारी थी। 27 जून को श्यामपुर पुलिस ने इसी मामले में 52,500 रुपये के नकली नोट बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उसी कार्रवाई से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और गिरोह के ठिकाने तथा उपकरणों तक पहुंच गई। इस दूसरी कार्रवाई में करीब 50 हजार रुपये के छपे नकली नोट, लैपटॉप, दो प्रिंटर और अन्य सामग्री बरामद होने से पुलिस ने पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने का दावा किया है।

ल्वारा ग्राम पंचायत का बड़ा फैसला, सार्वजनिक आयोजनों में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध

रुद्रप्रयाग। ग्राम पंचायत ल्वारा ने सामाजिक सुधार और गांव के समग्र विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पंचायत क्षेत्र में आयोजित होने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों, सामुदायिक आयोजनों और सामाजिक समारोहों में शराब परोसने और उसके सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। पंचायत के इस फैसले को ग्रामीणों ने सामाजिक सौहार्द, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और नशामुक्त समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।ग्राम प्रधान आशा देवी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वन पंचायत, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। बैठक में गांव के सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सार्वजनिक आयोजनों में शराब पर रोक से गांव का सामाजिक वातावरण और अधिक स्वस्थ एवं सकारात्मक बनेगा। इससे आपसी भाईचारा मजबूत होगा, विवादों में कमी आएगी और युवा पीढ़ी को नशामुक्त जीवन अपनाने की प्रेरणा मिलेगी।बैठक में ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास को लेकर भी विस्तृत मंथन किया गया। स्वच्छता अभियान को नियमित रूप से चलाने, पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण करने, पेयजल एवं सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचाने तथा युवाओं और महिलाओं की विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।ग्रामीणों ने सामाजिक एकता, पारंपरिक संस्कृति और लोक परंपराओं के संरक्षण को प्राथमिकता देने का संकल्प भी लिया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि पंचायत क्षेत्र में सभी विकास कार्य जनसहभागिता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किए जाएंगे, ताकि ल्वारा ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा सके।बैठक के अंत में सभी ग्रामीणों ने नशामुक्त, स्वच्छ, हरित एवं समृद्ध ग्राम पंचायत के निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया। पंचायत प्रतिनिधियों ने विश्वास जताया कि बैठक में लिए गए निर्णय गांव के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को नई दिशा देंगे तथा अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेंगे।बैठक में पूर्व प्रधान कैलाश चन्द्र पुरोहित, दरवान भट्ट, महेश प्रसाद बगवाड़ी, राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला, माया बगवाड़ी, पार्वती बगवाड़ी, मोनिका बुटोला, चन्द्रवती बुटोला, लक्ष्मी फर्स्वाण, आशा सेमवाल, कविता शुक्ला, मंजू राणा, शीला भट्ट, सुनीता भट्ट, शशि देवी, अनीता देवी, प्रियंका देवी, आशा गुसाईं, पूजा देवी, रघुवीर लाल, मीनाक्षी देवी, लक्ष्मी देवी, रोशनी देवी सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत, एक घायल

टिहरी संवाददाता। मंगलवार सुबह बस व बाइक की आमने–सामने हुई भिड़त के बाद जहां एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गयी वहीं दूसरा व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस मृतक व घायल की पहचान में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार आज सुबह समय 9.05 पर कर्णप्रयाग जा रही बस संख्या यूके 11 पीए 0316 एवं मोटर साइकिल संख्या यूके12 जी–1916 की एनएच 07 पर मूल्यागांव के समीप जबरदस्त भिड़ंत होने पर मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई एवं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे तहसील प्रशासन द्वारा राजकीय वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागी देवप्रयाग पहुंचाया गया। दोनों का नाम पता अभी मालूम नहीं हो पाया है।



मसूरी में बारिश से मौसम हुआ खुशगवार, पर्यटकों ने उठाया मौसम का आनंद

मसूरी। पर्यटन नगरी में बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया। विगत दिनों से मौसम में उमस हो रही थी व मसूरी में भी लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था। लेकिन बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया व पर्यटकों ने मौसम का जमकर आनंद लिया।पर्यटन नगरी में भी इस बार बारिश न होने से उमस होने लगी थी जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी हालांकि मैदानी क्षेत्र से आये लोगों को यह मौसम सुहाना लग रहा थाए लेकिन स्थानीय लोगों को उमस के कारण परेशानी हो रही थी व लोग बारिश का इंतजार कर रहे थेए हालांकि देहरादून में गत दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है लेकिन मसूरी में बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन आज सुबह से ही मौसम खराब रहा व पूरा शहर घने कोहरे की चपेट में रहा व दोपहर के बाद अचानक जमकर बारिश शुरू हो गयी जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली व उमस में कमी आयी व हल्की ठंड का अहसास हुआ। पर्यटन सीजन के चलते इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी में हैं जिन्होंने बारिश का जमकर आनंद लिया व यहां के खुशगवार मौसम के बीच बारिश रूकने पर मालरोड पर जाकर आनंद लिया। बारिश करीब एक घंटा रही व उसके बाद बारिश हल्की हो गयी लेकिन उसके बावजूद पर्यटक मालरोड पर छाता व बरसाती लेकर घूमते र ह ।

रुद्रपुर के विकास को लेकर मेयर विकास शर्मा ने कुमाऊँ आयुक्त दीपक रावत से की मुलाकात



जलभराव की स्थायी समस्या के समाधान हेतु 16.61 करोड़ की आरसीसी नाला परियोजना को बताया प्राथमिकता

हल्द्वानी। रुद्रपुर नगर निगम के महापौर विकास शर्मा ने मंगलवार को हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में कुमाऊँ आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव '' से शिष्टाचार भेंट कर शहर के समग्र विकास एवं जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान रुद्रपुर में बरसात के समय होने वाली जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान को प्रमुखता से उठाया गया।महापौर विकास शर्मा ने कुमाऊँ आयुक्त को अवगत कराया कि रुद्रपुर शहर में प्रत्येक वर्ष वर्षाकाल के दौरान कई क्षेत्रों में गंभीर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे आम नागरिकों, व्यापारियों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए आंतरिक मार्ग संख्या–87 में अटरिया मोड़ से डीडी चौक होते हुए त्रिशूल चौक तक सड़क के दोनों ओर आरसीसी नालों का निर्माण अत्यंत आवश्यक है।महापौर ने बताया कि नगर निगम द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है। प्रस्तावित योजना की अनुमानित लागत लगभग 16 करोड़ 61 लाख 61 हजार रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना शहर की जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ–साथ भविष्य में होने वाले जलभराव की समस्या को काफी हद तक समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।उन्होंने कुमाऊँ आयुक्त से अनुरोध किया कि इस जनहितकारी परियोजना के लिए जिला विकास प्राधिकरण अथवा अन्य उपयुक्त माध्यमों से आवश्यक वित्तीय स्वीकृति और धनराशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके। महापौर ने कहा कि रुद्रपुर तेजी से विकसित हो रहा औद्योगिक एवं व्यावसायिक शहर है, इसलिए यहां की आधारभूत सुविधाओं को भी उसी गति से विकसित किए जाने की आवश्यकता है।कुमाऊँ आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने महापौर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को गंभीरता से सुना और संबंधित परियोजना का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शहरी विकास और जनहित से जुड़े कार्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।बैठक के दौरान रुद्रपुर शहर के समग्र विकास, आधारभूत ढांचे के विस्तार, यातायात व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली, नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। दोनों अधिकारियों के बीच शहर के सुनियोजित विकास और भविष्य की आवश्यकताओं को लेकर भी विचार–विमर्श किया गया।महापौर विकास शर्मा ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार और प्रशासन के सहयोग से रुद्रपुर में विकास कार्यों को और गति मिलेगी तथा नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। वहीं शहरवासियों को भी इस मुलाकात से विकास परियोजनाओं के जल्द धरातल पर उतरने की उम्मीद जगी है।रुद्रपुर की जलभराव समस्या लंबे समय से स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण रही है। ऐसे में यदि प्रस्तावित आरसीसी नाला परियोजना को स्वीकृति मिलती है तो इससे न केवल जल निकासी व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि शहर के कई प्रमुख क्षेत्रों को बरसात के दौरान होने वाली परेशानियों से भी राहत मिल सकेगी।

2 जुलाई को ऊधमसिंहनगर में होगा आपदा प्रबंधन तंत्र का बड़ा परीक्षण



राज्य स्तरीय मानसून मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा, पांच स्थानों पर बनाए गए आपदा परिदृश्य

रुद्रपुर। मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आगामी 2 जुलाई को पूरे उत्तराखण्ड में राज्य स्तरीय मानसून मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आयोजित होने वाली इस व्यापक मॉक ड्रिल के माध्यम से विभिन्न विभागों की आपदा प्रतिक्रिया क्षमता, राहत एवं बचाव तंत्र, संसाधनों की उपलब्धता तथा आपसी समन्वय की वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया जाएगा।मंगलवार को सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी जनपदों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि मॉक ड्रिल को पूरी तरह वास्तविक आपदा परिस्थितियों के अनुरूप आयोजित किया जाए, ताकि आपात स्थिति में विभागों की कार्यप्रणाली, त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय क्षमता का सही आकलन किया जा सके।बैठक के दौरान प्रदेश के सभी जनपदों ने पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से अपनी–अपनी तैयारियों की जानकारी साझा की। ऊधमसिंहनगर की ओर से अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण देते हुए जिले में प्रस्तावित मॉक ड्रिल की रूपरेखा प्रस्तुत की।उन्होंने बताया कि जिले में पांच संवेदनशील स्थानों का चयन किया गया है, जहां अलग–अलग संभावित आपदा परिस्थितियों के आधार पर अभ्यास किया जाएगा। काशीपुर में 20 नंबर पावर हाउस के क्षतिग्रस्त होने, बाजपुर के लेबरा पुल के क्षतिग्रस्त होने, रुद्रपुर मार्ग पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित होने, सितारगंज के बमनपुरी पुल के तटबंध टूटने तथा खटीमा के गौशाला क्षेत्र में जलभराव की स्थिति को आधार बनाकर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।इन परिदृश्यों के माध्यम से विभिन्न विभागों की त्वरित प्रतिक्रिया, राहत एवं बचाव कार्यों की गति, संसाधनों की उपलब्धता, आपसी समन्वय तथा आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था की प्रभावशीलता का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही संभावित आपदा की स्थिति में जनहानि और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों का भी अभ्यास किया जाएगा।बैठक में इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम (आईआरएस) से जुड़े अधिकारियों की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई। तहसील स्तर के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), पुलिस, पैरामिलिट्री बलों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों की तैनाती और जिम्मेदारियों को लेकर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए।सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि उत्तराखण्ड भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य है, जहां मानसून के दौरान भूस्खलन, अतिवृष्टि, जलभराव, सड़क अवरोध और पुलों को नुकसान जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे में मॉक ड्रिल के माध्यम से सभी विभागों की तैयारियों का परीक्षण करना बेहद आवश्यक है, ताकि वास्तविक आपदा के समय त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।बैठक के अंत में सभी अधिकारियों और विभागों को मॉक ड्रिल के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं दी गईं। यह भी बताया गया कि मॉक ड्रिल के दौरान किए गए अभ्यास और उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. उत्तम सिंह नेगी, प्रभारी अधिकारी गौरव पाण्डेय, नगर आयुक्त शिप्रा जोशी, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग अनिल पांगती, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ईशान कटारिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।राज्य स्तरीय यह मॉक ड्रिल न केवल आपदा प्रबंधन तंत्र की तैयारियों को परखेगी, बल्कि भविष्य में आने वाली किसी भी आपदा से निपटने के लिए प्रशासनिक मशीनरी को और अधिक सक्षम एवं सजग बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

स्वामी,प्रकाशक,एवं संपादक भूपेश छिम्वाल द्वारा मुद्रक चौहान प्रिंटर्स सिंह कॉलोनी गली न-4,उधमसिंहनगर उत्तराखंड-263153,से मुद्रित व् कार्यालय-विला न-1,पुखराज कॉलोनी, औप आर.ए.एन पब्लिक स्कूल,भूरारानी उधमसिंहनगर उत्तराखंड-263153 से प्रकाशित संपादक- 6395804600
पीआरबी एक्ट की धारा 4 के अनुसार समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र रुद्रपुर न्यायालय होगा। संपादक- भूपेश छिम्वाल मो -7088770888